

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 15, शक 1941

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2019

#### शुद्धिपत्र

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22-08-2019 के चतुर्थ पंक्ति में “विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-निवेश आयुक्त, आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली” के स्थान पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-निवेश आयुक्त, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) (मुख्यालय दिल्ली) पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

**आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग**  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ-19-48/2010/25-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02-07-2015 एवं 30-01-2016 को अतिष्ठित करते हुए भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पत्र दिनांक 05-11-2015 एवं दिनांक 25-07-2019 के अनुपालन में प्रधान मंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं उसकी समीक्षा हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन करता है :—

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2. श्री रणविजय सिंह जूदेव, माननीय राज्यसभा सदस्य	सदस्य
3. श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, माननीय लोक सभा सदस्य	सदस्य
4. श्रीमती गोमती साय, माननीय लोक सभा सदस्य	सदस्य
5. श्री यू. डी. मिंज, माननीय विधायक-कुनकुरी	सदस्य
6. श्री विनय भगत, माननीय विधायक-जशपुर	सदस्य
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास/गृह/वित्त एवं योजना/नगरीय विकास/महिला एवं बाल विकास/स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन/उद्योग एवं वाणिज्य विभाग.	सदस्य
8. पुलिस महानिदेशक/आयुक्त, महिला एवं बाल विकास/आयुक्त, स्कूल शिक्षा/आयुक्त, उच्च शिक्षा/विकास आयुक्त/संचालक, नगरीय प्रशासन/आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य.	सदस्य
9. कलेक्टर, जशपुर	सदस्य
10. कलेक्टर जशपुर द्वारा नामित एजेंसी जिसने पूर्व में बेसलाईन सर्वे रिपोर्ट तैयार किया हो.	सदस्य
11. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा. तथा अनु. जाति विकास विभाग	नोडल अधिकारी
12. श्रीमती सुभद्रा सलाम-कांकेर	सदस्य
13. श्रीमती शारदा वर्मा-रायपुर	सदस्य
14. श्री अशोक जगते-सूरजपुर	सदस्य
15. श्रीमती नीना रावतिया-बीजापुर	सदस्य
16. श्रीमती सरला सिंह	सदस्य
17. श्री शरन सिंह-मनेन्द्रगढ़	सदस्य
18. श्री रामकृष्ण साहू	सदस्य
19. श्रीमती लीलावती कमरो	सदस्य
20. श्रीमती संगीता सोनवानी-पटना (बैकुण्ठपुर)	सदस्य
21. श्रीमती ज्योति कश्यप	सदस्य
22. श्री शाहिद इकबाल-माहेनूर एजुकेशन सोसायटी, बैरन बाजार, रायपुर	सदस्य
23. श्री मनजीत सिंह सलूजा-श्री गुरू सिंग सभा बसना (महासमुंद)	सदस्य
24. श्री सरजियस मिंज-जशपुर	सदस्य
25. श्री सुरेन्द्र शर्मा-बलौदाबाजार	सदस्य
26. श्री राकेश गुप्ता-अंबिकापुर	सदस्य
27. श्री रजनू नेताम-नारायणपुर	सदस्य

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ-16-34/2016/25/2.—राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गों की जाति सूची में शामिल निम्नांकित जातियों के उनके नाम के समक्ष कॉलम 04 में वर्णित क्षेत्रीय बंधन को कोष्टक सहित सूची से विलोपित करता है :—

क्र.	जाति का सरल क्रमांक	जाति का नाम	वर्णित, क्षेत्रीय बंधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	20	धोबी	( भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर )
2.	21	मीणा	( विदिशा जिले की सीरौज एवं लटेरी, तहसील को छोड़कर )
3.	47	पनिका	( छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी एवं शहडोल जिलों को छोड़कर )
4.	57	कोटवाल	( भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, साजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोड़कर ).

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 नवम्बर 2019

क्रमांक/एफ-16-34/2016/25/2.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गों की जाति सूची के सरल क्रमांक 12 में अंकित प्रविष्टि जालारनलु (बस्तर जिले में) के स्थान पर जालारनलु (बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा जिलों में) प्रतिस्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

## गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ 7-07/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री पवन देव (भापुसे 1992), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर को दिनांक 14 अक्टूबर 2019 से 23 अक्टूबर 2019 (कुल 10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 12 एवं 13 अक्टूबर 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

- अवकाश से लौटने पर श्री देव (भापुसे) आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
- अवकाश काल में श्री देव (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.
- प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देव (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

प्रारूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6919/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	सेम्हरबांधा प.ह.नं. 20	0.121 हे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के मोंगरा एनीकट के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 11-11-2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन सेम्हरबांधा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के मोंगरा एनीकट के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	08
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6935/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	कातुलवाड़ा प.ह.नं. 27	0.065 हे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के मोंगरा एनीकट के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 14-11-2019 को (समय) पूर्वाह्न 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन पीपरखार पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के मोंगरा एनीकट के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6940/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	डोंगरगांव प.ह.नं. 04	0.068 हे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के हालमकोड़ो जलाशय के नहर नाली में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 07-11-2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन डोंगरगांव पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के हालमकोड़ो जलाशय के नहर नाली में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाए किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6941/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	हज्जूटोला प.ह.नं. 04	0.137 हे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के हालमकोड़ो जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 23-11-2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन तिरपेमेटा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के हालमकोड़ो जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

प्रारूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6942/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	छछानपहरी प.ह.नं. 11	0.340 हे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के बहोरनभेड़ी एनीकट/काजवे में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 21-11-2019 को (समय) पूर्वाह्न 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन छछानपहरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के बहोरनभेड़ी एनीकट/काजवे में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.



राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6943/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	हालमकोड़ो प.ह.नं. 03	0.173 हे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के हालमकोड़ो जलाशय के बांध पार में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 18-11-2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन हालमकोड़ो पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के हालमकोड़ो जलाशय के बांध पार में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

प्रारूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/6944/भू-अर्जन/2018.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	सालहेकुसुमकसा प.ह.नं. 01	1.168 हे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के पेन्दलकुही जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 04-11-2019 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन कुसुमकसा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के पेन्दलकुही जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयप्रकाश मोर्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग**

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/क/3606/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	कोटा	दारसागर	2.35/0.951	रतखण्डी व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 20-11-2019 को (समय) 11.00 बजे (स्थान ग्राम पंचायत भवन दारसागर (कूपाबांधा) पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रतखण्डी व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	4
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां-उल्लेखित भूमि पर रतखण्डी व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	10.00 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व  
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

क्रमांक/6953/प्र.क्र. 04 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-सिरलगढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.044 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41/3	0.757
64	0.287
योग	02 1.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

क्रमांक/6954/प्र.क्र. 07 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-आतरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
412	0.121
योग	01 0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

क्रमांक/6955/प्र.क्र. 06 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-मोहड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.635 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
351	0.081
334/1	0.012
320/1	0.049

(1)	(2)	(1)	(2)
254/2	0.012	659/1	0.356
317/7	0.028	509/1	0.275
374/4	0.049	683/5	0.024
318/1	0.012	683/3	0.064
375	0.109	683/2	0.053
422/1	0.190	683/6	0.024
354/1	0.093	683/1	0.049
		683/4	0.053
योग	10	523/2	0.077
		536/3	0.040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण.		540/4	0.138
		563/2	0.041
		563/4	0.231
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.		563/8	0.041
		631/3	0.253
		633/3	0.129
		523/3	0.150
राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2019		629/2	0.405
		673/2	0.328
क्रमांक/6956/प्र.क्र. 08 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		596/3	0.093
		596/2	0.243
		656/3	0.093
		655/2	0.137
		664/3	0.328
		664/1	0.162
		639/5	0.032
		639/7	0.089
		664/2	0.162
		557/6	0.178
		666	0.142
		396/2	0.695
		672/4	0.045
		672/3	0.044
		616/1	0.065
		575/3	0.303
		619/5	0.044
		629/1	0.182
		639/8	0.073
		629/3	0.182
		673/1	0.328
		616	0.194
		योग	49
			8.331
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.	

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

## अनुसूची

क्रमांक/6957/प्र.क्र. 05 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-राजनांदगांव  
(ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी  
(ग) नगर/ग्राम-बुटाकसा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.275 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
198/4	0.275
योग	01 0.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जय प्रकाश मौर्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व  
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2019

क्रमांक 01/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर  
(ख) तहसील-बिल्हा  
(ग) नगर/ग्राम-संबलपुरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.240 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
87/1	0.202
86/4, 86/11	0.125
86/3	0.162
41/2	0.081
41/4	0.065
42	0.146
310/8	0.257
46/1	0.121
46/2	0.049
245	0.032
योग	11 1.240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2019

क्रमांक 04/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर  
(ख) तहसील-बिल्हा  
(ग) नगर/ग्राम-खन्तहा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.611 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	14/4	0.089
		14/1	0.085
7	0.061	13/1	0.004
8/2	0.081	14/3	0.101
8/6	0.024	14/5	0.040
8/5	0.012	35	0.081
98/1	0.182	36/1	0.089
96/1	0.101	37/3	0.053
103/4	0.049	37/2	0.045
103/1	0.073	38/1,	0.141
8/4	0.028	38/3	
		55	0.024
योग	9	56/1	0.061
		57	0.036
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार		270/1	0.008
बैराज परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.		54/3	0.040
		53	0.012
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी		58	0.028
(राजस्व), बिल्हा में किया जा सकता है.		59/1	0.024
		60	0.073
		95/3	0.016
बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2019		96	0.101
		97	0.045
क्रमांक 05/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस		98/2	0.045
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में		98/1	0.109
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक		99	0.057
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और		95/2	0.024
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार		155/4	0.170
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा		155/3	0.040
जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता		155/5	0.004
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		154/1	0.024
		7	0.206
अनुसूची		154/2	0.134
		151/1	0.028
(1) भूमि का वर्णन—		151/2	0.077
(क) जिला-बिलासपुर		148/1	0.097
(ख) तहसील-बिल्हा		147/2	0.057
(ग) नगर/ग्राम-डोकलाडीह		148/2	0.032
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.296 हेक्टेयर		148/4	0.004
		11/1	0.040
		12/4	0.004
खसरा नम्बर	रकबा	12/3	0.028
	(हेक्टेयर में)	11/3	0.053
(1)	(2)	10/6	0.045
		10/1	0.049
5/3	0.129	10/2	0.073
4	0.170	42	0.004
14/7	0.093	41/1	0.036

(1)	(2)	(1)	(2)
43/1	0.004	खसरा नम्बर	रकबा
43/2	0.053		(हेक्टेयर में)
46/4	0.049	(1)	(2)
46/1	0.053		
163/1	0.061	14/1	0.004
163/3	0.008	14/2	0.097
12/1	0.040	13	0.162
		19	0.081
योग	58	20	0.069
	3.296	29/1	0.113
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार		32	0.121
बैराज परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.		42	0.089
		51	0.008
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी		22/1	0.202
(राजस्व), बिल्हा में किया जा सकता है.		40	0.004
		16	0.093
		31/3	0.101
		49/2	0.020
		60/1	0.008
बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2019		33	0.202
		41	0.182
क्रमांक 06/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस		43	0.028
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में		46	0.008
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक		47	0.053
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और		48	0.045
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार		6/43	0.028
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा		49/1	0.049
जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता			
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		योग	23
			1.767

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-निपनिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.767 हेक्टेयर

#### (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

#### (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.